

गैर-रपिओरटेबल

00030000 एक्सएनटीएक्स2एक्सईएंटेक्स एक्ससेंटीक्स4एक्सइंटेक्स एक्सईएनटीएक्स1एक्सईएंटेक्स
00000 0000010000

2020 का सविलि 000000000000
(एक्स. ई. एन. टी. एक्स1एक्सई. एम. एस. के 000 (0) 00.26267 से नकिल रहा है)

□□□□ □□□□1□□□□

अपीलारथी (ओं)

बनाम

एकस. ई. एन. टी. एकस0एकस. ए. आई. और एस. ड. एम1एकस।

उत्तरदाता (ओं)

के साथ

2020 का सविलि ००००००००००
(एक्स. ई. एन. टी. एकस1एकसई. एम. एस. के ००० (०) ००. 25464 से नकिल रहा है)

2019 का ँ.ं.(ं) ँ. 1395

2019 का ०.०.(०) ००. 1461

2020 का सविलि 000000000000
(0000000000000000 (0) संख्या से नकिल रहा है।

2020 का सविलि 000000000000
(00000010000000 के 000000000000792 से नकिल रहा है)

2020 का सविलि ००००००००००
(०००० (०) ००.2493 की डायरी संख्या (ओं)।

2020 का सविलि 000000000000
(00000000000000 (0) संख्या से नकिल रहा है।

00000 का सविलि 000001000000
(0000 (0) 00.2494 की डायरी संख्या (ओं)।

2020 का सविलि ००००००००००
(००००००००००००० (०) ००.26724 से बाहर नकिलते हुए)

0

संख्या का सविलि 000001000000
(000000000000 (0) संख्या से नकिल रहा है।

2020 का सविलि 000000000000
(एक्स. ई. एन. टी. एक्स1एक्सई. एम. एस. के 0000 (0) 00.1155 से नकिल रहा है)

जे यू डी जी एम ई एन टी

एल. एक्स. ई. एन. टी.एक्स0एक्सईएनटीएक्स, जे.

1. केंद्र द्वारा जारी अधिसूचनाओं की वैधता

भारतीय चकित्सा परिषद (इसके बाद के रूप में संदर्भित, '

केंद्रीय परिषद) और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद

अखलि भारतीय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश नर्धारित करना

स्नातक में प्रवेश के लिए परीक्षा (संक्षेप में, '000000000000')

पाठ्यक्रम (000000000000, 00000010000000, 000000200000 और 000000300000) और न्य

उक्त परीक्षा में योग्यता अंक, में उत्पन्न होते हैं

ऊपर अपील और रटि याचिकाएँ। ये अधिसूचनाएँ

000000000000 स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करें

शैक्षणिक वर्ष 2019-000000000000 से। इसी तरह, की वैधता

000000000000 स्नातकोत्तर की शुरुआत करने वाली अधिसूचना

स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा (0000-000000000000)

पाठ्यक्रम (00-आयुर्वेद) और न्यूनतम नर्धारित करना

उपरोक्त अपीलों में योग्यता अंक भी उत्पन्न होते हैं।

2. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी, सद्धि, सोवा रगिपा और होम्योपैथी (संक्षेप में, 'संक्षेप'), सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया और संक्षेप में छात्रों को प्रवेश देने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों के तहत 2018-2019 में केवल संक्षेप में योग्यता सूची के आधार पर, द्वारा आयोजित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (संक्षेप में) मौजूदा नियमों और आरक्षण नीतियों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों का। न्यूनतम अंडर में प्रवेश की पात्रता के लिए योग्यता चिह्न स्नातक पाठ्यक्रम संक्षेप में प्रतिलिपि पर निर्धारित किए गए थे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचितों के लिए न्यूनतम अंक जनजातियों और अन्य पछिड़े वर्गों को संक्षेप में निर्धारित किया गया था प्रतिलिपि। प्रतिलिपि इस आधार पर निर्धारित किया जाएगा अखिल भारतीय सामान्य योग्यता सूची में प्राप्त अंकों की संख्या संक्षेप में. इसके बाद, दिनांक 07.12.2018 की अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय परिषद ने भारतीय चिकित्सा केंद्र की शुरुआत की परिषद (भारतीय में शिक्षा के न्यूनतम मानक) चिकित्सा) संशोधन विनियम, 2018 (इसके बाद जसि'2018 विनियम) के रूप में संदर्भित किया गया है। चिकित्सा केंद्रीय परिषद (शिक्षा के न्यूनतम मानक)

3. गुरु रवदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, होशियारपुर,
पंजाब ने प्रवेश के लिए 31.07.2019 पर एक विवरण पुस्तिका जारी की
न्यूनतम निर्धारित करने वाले 000000, 00000200000 और 00001000000 पाठ्यक्रम
00000000000 में अंक और अंडर में प्रवेश के लिए मानदंड
स्नातक पाठ्यक्रम। 2019 के सविलि राइट 0000000000 में
00000000000 कॉलेजों के प्रबंधन द्वारा दायर, उच्च
पंजाब और हरियाणा की अदालत ने एक अंतरिम आदेश पारित किया
06.09.2019 छात्रों को अंडर में प्रवेश की अनुमति देना
इसके बिना स्नातक पाठ्यक्रम (00000000000, 00000200000 और 00001000000)
छात्रों को न्यूनतम आवश्यकता प्राप्त करने पर जोर देना
00000000000 में प्रतिलिपि। इसी तरह के आदेश पारित किए गए थे
पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय अन्य रटिवाचिकाओं में।
आयुर्वेदिक द्वारा दायर सभी रटिवाचिकाएँ और
होम्योपैथिक कॉलेजों को उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था
पंजाब और हरियाणा दिनांकित अपने फैसले द्वारा 18.12.2019।
उक्त निर्णय से व्यथित, महाविद्यालयों के साथ-साथ
छात्रों ने हमारे सामने ये विशेष अनुमतिवाचिकाएँ दायर कीं।
छात्रों द्वारा दायर किए गए अन्य 000 हैं जो मांग कर रहे हैं।
स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश (00000000000, 00000100000 और
शैक्षणिक वर्ष के लिए 0000)। प्रवेश थे
के आधार पर संस्थानों में छात्रों को प्रदान किया गया

इस पर जोर दिए बिना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश

2018 वनियमों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड।

0000000000 में न्यूनतम अंक प्राप्त करना। केंद्रीय परिषद

अंतरिम आदेशों से व्यथित होकर कुछ 0000000000 भी दाखल किए हैं।

प्रवेश की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालयों द्वारा पारित

000000000000 पात्रता पर जोर दिए बिना छात्र

स्नातक के साथ-साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

4. जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह बटु जो हमारे लिए उत्पन्न होता है

वर्ष यह है कि क्या छात्र प्रवेश चाहते हैं

स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए (000000000000, 00000010000000, 000000200000 और

000000000000) और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को अस्वीकार किया जा सकता है।

इस आधार पर स्वीकार किया कि उन्होंने 000000000000 नहीं लिया था

या कि उन्हें निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत नहीं मिला

000000000000 वनियमों के अनुसार। इसे संदर्भित करना सुविधाजनक होगा।

2020 के तथ्य जो दायर किए गए हैं

पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ और

हरियाणा दिनांक 18.12.2019 सविलि राइट 000000000000 में

प्रमुख पदार्थ के रूप में 000000000000 (0 0 0) का।

5. उच्च न्यायालय में, इसकी ओर से तर्क दिया गया था

जिन संस्थानों ने लिखित याचिका दायर की थी कि 2018

नियम भारतीय चिकित्सा केंद्र के अधिकार से परे हैं।

परषिद अधनियिम, १९५६ (इसके बाद 'अधनियिम' के रूप में संदर्भित)।

तर्क दिया गया था कि अखिल भारतीय परीक्षा की शुरुआत

१९५६ का रूप वनियिमन बनाने से परे है।

धारा 36 के तहत केंद्रीय परषिद का प्राधिकरण

अधनियिम. रलियांस को रटि याचिकाकर्ताओं द्वारा इस पर रखा गया था

तथ्य यह है कि १९५६ परीक्षा इसके लिए शुरू की गई थी

प्रावधानों में संशोधन करने के बाद ही १९५६ और १९५७ पाठ्यक्रम

भारतीय चकित्सा परषिद अधनियिम, 1956 और दंत चकित्सक अधनियिम

1948 क्रमशः। संदर्भ दिया गया था

धारा 10 में किए गए संशोधन और इसकी धारा १९५६

अधनियिम और दोनों में धारा 10-क की शुरुआत

उपरोक्त अधनियिम। यह तर्क दिया गया था कि बिना

के प्रावधानों में संशोधन करने का एक समान अभ्यास करना

केंद्रीय परषिद को ऐसा करने का अधिकार देने वाला अधनियिम

प्रवेश परीक्षाओं को नियंत्रित करने वाले नियम, केंद्रीय

परषिद ने जल्दबाजी में 2018 वनियिम बनाए।

अदालत ने रटि याचिकाओं को खारज कर दिया

आयोजित करके संस्थानों की ओर से उठाए गए विवाद

कदिनांक 07.12.2018 विवादित नियम ठीक थे

केंद्रीय परषिद द्वारा प्रदत्त शक्तियों के भीतर

अधनियिम. स्नातक पाठ्यक्रमों में किए गए प्रवेश

शैक्षणिक वर्ष के लिए बना 2018 के छात्रों को एक्सईएनटीएक्स1एक्सईएनजीएक्स-एक्सईएंडएक्स0

पात्रता को अस्थिर पाया गया क्योंकि वे थे

2018 वनियमों के विपरीत। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

छात्र किसी भी इक्विटी का दावा नहीं कर सकते क्योंकि अंतरिम

जनिक आधार पर प्रवेश दिए गए थे

छात्रों ने निर्धारित किया कि उनका प्रवेश विषय होगा

लेखन याचिकाओं के अंतिम परिणाम तक।

6. यह संस्थाओं की ओर से तर्क दिया गया था और

छात्रों को लगता है कि 2018 वनियम अधिनियम के अधिकार से परे हैं।

केंद्रीय परिषद को ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है

अखिल भारतीय प्रवेश की शुरुआत के लिए नियम

अधिनियम की धारा 2018 के तहत जाँच। यह मानते हुए कि

नियम सामान्य नियम बनाने के तहत बनाए गए थे

शक्तियाँ, संस्थाओं की ओर से समर्पण और

छात्रों का कहना था कि 2018 वनियम इसमें नहीं हैं।

धारा एक्स. ई. एन. टी. एक्स1एक्सई. एम. एस. (1) के तहत "अधिनियम के उद्देश्यों" के अनुरूप होना।

अधिनियम का। प्रस्तुतियों के समर्थन में, संदर्भ था

किए गए संशोधनों में किया गया

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2018 और दंत चिकित्सक अधिनियम

वनियम बनाने से पहले 2018 जसिके द्वारा अखिल भारतीय

स्नातक और पद में प्रवेश के लिए परीक्षाएँ

स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए गए। आगे की प्रस्तुति

छात्रों और संस्थानों में से यह था कि नहीं है।

के पाठ्यक्रम के रूप में आयुर्वेदिक पाठ्यक्रमों के लिए संरचित

पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम से पूरी तरह से अलग है या

पाठ्यक्रम।

7. इसके विपरीत, सुश्री पकी आनंद, विद्वान अतिरिक्त

केंद्रीय परिषद की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल

प्रस्तुत किया कि 2018 विनियम पूरी तरह से मान्य है

शक्त के वैध प्रयोग में किया गया है

केंद्रीय परिषद को धारा 36 के तहत सम्मानित किया गया

अधिनियम. सुश्री आनंद ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 22

शिक्षा के न्यूनतम मानकों से संबंधित

भारतीय चिकित्सा में प्रवेश करने की शक्ति शामिल है।

स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा।

सुश्री आनंद के अनुसार, केंद्रीय परिषद को बदनाम नहीं किया गया है

अधिनियम की धारा के रूप में विनियम बनाने की शक्ति

परिषद को आम तौर पर लागू करने के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाता है

अधिनियम के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। उन्होंने आग्रह किया कि न्यूनतम

अंडर में प्रवेश के लिए निर्धारित योग्यता प्रतिलिपि

स्नातक पाठ्यक्रम (के, 2, 1 और 3)

न्यूनतम बनाए रखने के लिए आवश्यक

शिक्षा के मानक। उन्होंने तर्क दिया कि सामान्य
पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मानक तय किए जाते हैं।
एक वसितृत अध्ययन और शुद्धता के आधार पर
इस तरह का निर्णय इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है।

8. भारतीय के प्रावधानों को संदर्भित करना प्रासंगिक है।

चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, १९५६०। अधिनियम की धारा ११(१) केंद्रीय परिषद को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है
भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक जो
मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं
भारत में विश्वविद्यालयों, बोर्डों या चिकित्सा संस्थानों द्वारा।
धारा ११(१) में प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय परिषद,
केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी
आम तौर पर अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विनियम।
धारा ११(१) (क), (ख) और (ग) निम्नलिखित हैं:

(क) पाठ्यक्रम और अध्ययन की अवधि और व्यावहारिक
शुरू किया जाने वाला प्रशिक्षण, परीक्षा के विषय
और उसमें प्राप्त की जाने वाली प्रवीणता के मानक,
अनुदान के लिए किसी भी विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सा संस्थानों में
मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता;
(ख) कर्मचारियों, उपकरणों, आवास के मानक,
भारत में शिक्षा के लिए प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं
दवा;

(ट) व्यावसायिक परीक्षाओं का संचालन,
परीक्षकों की योग्यताएँ और शर्तें
ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश;
(पी) कोई भी मामला जिसके लिए इस अधिनियम के प्रावधान के तहत
नियमों द्वारा किया जाए। "

9. हम इस पर किए गए तर्क से सहमत हैं

छात्रों और संस्थानों की ओर से जो परिचित होते हैं

अखिल भारतीय परीक्षा अनुभाग द्वारा कवर नहीं की जाएगी।

अधिनियम के 0000000000 (0), (जे) और (के)। हालाँकि, धारा 36 (पी) का उल्लेख है

अधिनियम के तहत किसी भी मामले के लिए जिसके लिए प्रावधान हो सकता है

नियमों द्वारा बनाए गए। हमारी विचारशील राय में,

अनुभाग 22 जो न्यूनतम मानकों से संबंधित है

भारतीय चिकित्सा में शिक्षा, सभी के विषय को शामिल करती है

भारत सामान्य प्रवेश परीक्षा। हम इसमें समर्थित हैं

पशु चिकित्सा में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा यह दृष्टिकोण

भारतीय परिषद बनाम भारतीय कृषि परिषद

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की अनुभाग 1 पर शोध करें।

अधिनियम भारतीय परिषद की धारा 0000000000 के अनुरूप है।

चिकित्सा अधिनियम. एक अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश

द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा परीक्षा शुरू की गई थी

0000000000 में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और एक परीक्षा

इसके अनुसार शैक्षणिक वर्ष से आयोजित किया गया था

1 (0000000000) 1 000010000000 300

1995-0000010000. की वैधता से संबंधित विवाद

वनियमों को इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करके हल किया गया था कि

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद तैयार करने के लिए अधिकृत है।

पशु चिकित्सा के मानकों को निर्धारित करने वाले नियम

शिक्षा और ऐसी शक्ति में बनाने की शक्ति शामिल है

प्रवेश और पशु चिकित्सा अनुदान से संबंधित वनियम

योग्यताएँ। इस न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्राधिकरण

प्रवेश के संबंध में नियम बनाने की आवश्यकता है

शिक्षा के मानकों को बनाए रखना। तत्काल मामला

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (ऊपर) इसलिए, हम हैं

यह राय कि 000000 वनियमों को नहीं कहा जा सकता है

अधिनियम के अधिकार में है।

10। स्नातक में प्रवेश की अंतिम तिथि

शैक्षणिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम 2019-0000000000 था।

अक्टूबर, एक्स. ई. एन. टी. एक्स0एक्सई. एम. एण्टएक्स और एक्सएएनटीएक्स2एक्स. आई. एफ. एस.

पाठ्यक्रम। की ओर से उठाए गए तर्कों में से एक

संस्थान और छात्र बड़ी संख्या में

पहले वर्ष में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी में सीटें

पाठ्यक्रम नहीं भरे गए हैं। उदाहरण के लिए, श्री पी. एस. पटवालिया,

वद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि 0000000000 सीटें हैं

वशिष्ट परस्थितियाँ। इसलिए, यह आदेश नहीं होगा

एक मसाल के रूप में माना जाता है।

13। दनांकित अधिसूचना 14.12.2018 से संबंधित

होम्योपैथी पाठ्यक्रम 000000 के समान हैं।

पाठ्यक्रम। यह होम्योपैथी की ओर से तर्क दिया गया था

ऐसे महाविद्यालय जो धारा 2 (2) में निर्धारित प्रक्रिया है

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 000000 (संक्षेप में,

संशोधन से पहले'000000 अधिनियम') का पालन नहीं किया गया था।

वर्णियों के अनुसार किया गया। की कमी को देखते हुए

उस समय, केंद्रीय परिषद द्वारा कोई जवाब दायर नहीं किया गया था

होम्योपैथी या भारत संघ द्वारा तथ्यात्मक को स्पष्ट करना

प्रक्रिया के गैर-अनुपालन से संबंधित स्थिति

वर्णियम बनाने के लिए 000000 अधिनियम के तहत निर्धारित।

उसी के दृष्टिकोण से, हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं

रटि याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा (000000)

000000 का। हम इसे याचिकाकर्ताओं के लिए खुला छोड़ते हैं कि वे इन्हें उठाएं।

उच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दे, यदि वे इसे उचित और उचित समझते हैं।

वभिन्न प्रस्तुतियों से नपिटना आवश्यक नहीं है।

द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया

हम छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देते हैं।

14। उपरोक्त टप्पणियों के लिए, सभी अपीलें
और रटि याचिकाओं का नपिटारा कर दिया जाता है।

..।।.

[एल. एक्स. ई. एन. टी.एक्स0एक्सईएनटीएक्स]

..।।.

[000000010000]

नई दिल्ली,
फरवरी 20, 0000000000।